



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 6, 1984/आषाढ़ 15, 1906

No. 314]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 6, 1984/ASADHA 15, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1984

कां.आं. 491(अ)/18कक/आईं.डीं.आरं.एं./84 :—
केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं. कां.आं. 602(अ)/18कक/आईं.डीं.आरं.एं./74 तारीख 9 अक्टूबर, 1974 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति निकाय को मैसर्स मोटर एण्ड मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड कलकत्ता का प्रबन्ध 9 अक्टूबर, 1974 से प्रारम्भ होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. कां.आं. 567/18कक/आईं.डीं.आरं.एं./78, तारीख 25 सितम्बर, 1978, द्वारा उक्त व्यक्ति निकाय के स्थान पर उक्त औद्योगिक उपक्रम के मुख्य

अधिशासक श्री पी.एन. रामचन्द्रन को प्रतिस्थापित किया गया था, और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. कां.आं. 866(अ)/18कक/आईं.डीं.आरं.एं./80, तारीख 29 अक्टूबर, 1980 द्वारा श्री के. एन. बैनर्जी, उप-महाप्रबन्धक, भारत हैवी इलेक्ट्रोक्स लिमिटेड कलकत्ता को उक्त औद्योगिक उपक्रम के प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था

और केन्द्रीय सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. कां.आं. 572(अ)/18कक/आईं.डीं.आरं.एं./79, तारीख 8 अक्टूबर, 1979, कां.आं. 738 (अ)/18कक/आईं.डीं.आरं.एं./81, तारीख 6 अक्टूबर, 1981, कां.आं. 263(अ)/18कक/आईं.डीं.आरं.एं./82, तारीख 8 अप्रैल 1982, कां.आं. 719(अ)/18कक/आईं.डीं.आरं.एं./82, तारीख 8 अक्टूबर, 1982, कां.आं. 8(अ)/18कक/आईं.डीं.आरं.एं./83, तारीख 7 जनवरी, 1983, कां.आं. 282 (अ)/18कक/आईं.डीं.आरं.एं./83, तारीख 8 अप्रैल, 1983, कां.आं. 718 (प)/18कक/आईं.डीं.आरं.एं./83 तारीख 7 अक्टूबर, 1983, कां.आं. 10(अ)/18कक/आईं.डीं.आरं.एं./84 तारीख 7 जनवरी 1984 और कां.आं. 271 (अ)

118कक/आई०डी०आर० ए०/84 तारीख 7 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त आदेश की अवधि तारीख 8 जुलाई, 1984 तक बढ़ा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश तीन मास की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहना चाहिए ;

अतः, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उप-धारा (2) के पञ्चक के साथ पठित धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि उक्त आदेश 8 अक्टूबर, 1984 तक जिसमें यह तारी भी सम्मिलित है और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा० सं० 2 (23)/79-मि०यू०एस०]

ए० पी० सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New, Delhi, the 6th July, 1984

No. S.O. 491(E)|18AA|IDRA|84.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 602(E)|18AA|IDRA|74, dated the 9th October, 1974 (hereinafter referred to as said Order) made in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government authorised a body of persons specified therein to take over the management of Messrs Motor and Machinery Manufacturers Limited, Calcutta, for a period of five years commencing from 9th October, 1974 and the said body of persons was replaced by Shri P. N. Ramachandran, Chief Executive of the said industrial undertaking by Order of the Government of India in the Ministry of Industry

(Department of Industrial Development) No. S.O. 567(E)|18AA|IDRA|78, dated the 25th September, 1978 and by Shri K. M. Banerjee, Deputy General Manager, Bharat Heavy Electricals Limited, Calcutta, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 866(E)|18AA|IDRA|80, dated 29th October, 1980, to take over the management of the said industrial undertaking;

And, whereas, by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 572(E)|18AA|IDRA|79, dated the 8th October, 1979, S.O. 738(E)|18AA|IDRA|81, dated the 6th October, 1981, S.O. 263(E)|18AA|IDRA|82, dated the 8th April, 1982, S.O. 719(E)|18AA|IDRA|82, dated the 8th October, 1982, S.O. 8(E)|18AA|IDRA|83, dated the 7th January, 1983, S.O. 282(E)|18AA|IDRA|83, dated the 8th April, 1983, S.O. 718(E)|18AA|IDRA|83, dated the 7th October, 1983, S.O. 10(E)|18AA|IDRA|84, dated the 7th January, 1984 and S.O. 271(E)|18AA|IDRA|84, dated the 7th April, 1984, the duration of the said Order was further extended upto and inclusive of the 8th July, 1984;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period of three months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA read with proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 8th October, 1984.

[F] No. 2(23)|79-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.